



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 676]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 19, 2013/फाल्गुन 28, 1934

No. 676]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 19, 2013/PHALGUNA 28, 1934

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  
(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2013

का.आ. 771(अ).—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) की धारा 20 की उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, चयन समिति की सिफारिश पर, एतद्वारा डॉ. एस. एम. कान्तिकर को समय-समय पर यथा संशोधित उपभोक्ता संरक्षण नियम, 1987 के साथ खंडित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 में निर्धारित शर्तों पर, 4 मार्च, 2013 के अपराह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 70 वर्ष की आयु के हो जाने तक, जो भी पहले हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1(3)/2012-सी.पी.यू.]

मनोज परिदा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND  
PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th March, 2013

S.O. 771(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) read with sub-section (3) of Section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government, on the recommendation of the Selection Committee, hereby appoints Dr. S. M. Kantikar as whole-time Member of the National Consumer Disputes Redressal Commission with effect from the forenoon of 4th March, 2013, for a period of five years, or until he attains the age of 70 years, whichever is earlier, on the terms and conditions prescribed in the Consumer Protection Act, 1986 read with the Consumer Protection Rules, 1987 as amended from time to time.

[F. No. 1(3)/2012-CPU]

MANOJ PARIDA, Jt. Secy.